बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्षः 24 ● अंकः 253 ● नई दिल्ली ● सोमवार 27 जुलाई 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्यः 3 रूपया ● पृष्ठः 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागारिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश; यमुनापार में हुआ जलभराव

नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच रविवार को भी राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली। पूर्वी दिल्ली के यमुनापार इलाके में कुछ देर की ही बारिश में जलभराव हो गया। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहेगा। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री दर्ज किया गया। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। दिन में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। बीच बीच मे धूप खिले रहने पर उमस से भी परेशानी होगी।

दिल्ली सरकार की अहम नियुक्तियां: अल्पसंख्यक और महिला आयोग को मिले नए अध्यक्ष, सदस्यों के नाम भी तय

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने दो महत्वपूर्ण आयोगों में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कहा कि ये फैसले सामाजिक समावेश, महिला सशक्तिकरण और सभी वर्गों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निर्मल जैन को नियुक्त किया गया है। वहीं, कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सरकार ने कहा कि वह समाज के सभी वर्गों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इन नियुक्तियों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण को मजबूती मिलेगी और सामाजिक सद्भाव व समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरक्षिका शर्मा झा और रेनू भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया है। सरकार का कहना है कि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई नियुक्तियों से आयोग की कार्यक्षमता को नई गति मिलेगी, जिससे महिलाओं तक न्याय, संरक्षण और सहायता की पहुंच पहले से अधिक प्रभावी हो सकेगी।

हल्ला बोल: पेपर लीक के बाद अब सड़क पर ई 20 के खिलाफ होगा आंदोलन, तहसीन पूनावाला ने बताई जगह और तारीख?

नई दिल्ली।

नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुए आंदोलन के बाद अब टीम भारत के संस्थापक तहसीन पूनावाला ने ई20 ईंधन नीति के खिलाफ नया आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि ई20 नीति सबसे खराब तरीके से लागू की गई नीतियों में से एक है। उनका कहना है कि अगर इस नीति में सही सुधार किए जाएं तो लोगों को 80 से 90 रुपये प्रति लीटर के बीच शुद्ध और बिना मिलावट वाला पेट्रोल मिल सकता है। इसी मांग को लेकर उन्होंने 31 जुलाई को दिल्ली में 'गाड़ी मार्च, गांधी मार्च' निकालने की घोषणा की है। तहसीन पूनावाला ने लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह मार्च इंडिया गेट से शुरू होगा और संसद मार्ग होते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरदीप पुरी के कार्यालय तथा आवास के बाहर पहुंचेगा। उन्होंने लोगों से अपनी कार, बाइक और अपनी आवाज के साथ आंदोलन में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह नागरिकों के अधिकार और उनकी पसंद का सवाल है।

ई20 नीति को लेकर तहसीन पूनावाला ने क्या दावा किया?

तहसीन पूनावाला ने कहा कि ई20 नीति देश की सबसे गलत तरीके से लागू की गई नीतियों में से एक है। उनका दावा है कि अगर इस नीति में सुधार किया जाए तो लोगों को शुद्ध पेट्रोल 80 से 90 रुपये प्रति लीटर के बीच उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में लोगों को अपनी जरूरत के मुताबिक ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए और नीति से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाने चाहिए।

आंदोलन कब और कहां होगा?

तहसीन पूनावाला ने घोषणा की कि 'गाड़ी मार्च, गांधी मार्च' 31 जुलाई 2026, शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। यह मार्च नई दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी नितिन गडकरी और हरदीप पुरी के कार्यालय और आवास के बाहर भी जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपनी कार और बाइक के साथ इस अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह 'मेरी गाड़ी, मेरा अधिकार' और 'मेरी बाइक, मेरी पसंद' का आंदोलन है। पूनावाला ने कहा कि यह अभियान केवल ईंधन की कीमतों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं को विकल्प देने और नीति में पारदर्शिता लाने की मांग भी है। उनका कहना है कि सरकार को ई20 नीति की समीक्षा करनी चाहिए और उन वाहन मालिकों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए, जिनके वाहन इस ईंधन मिश्रण से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अपने अभियान के तहत 'गाड़ी मार्च-गांधी मार्च' और मेरी गाड़ी-मेरा अधिकार जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया और लोगों से बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने की अपील की।

आंदोलन की मुख्य मांगें क्या हैं?

तहसीन पूनावाला ने आंदोलन के लिए कई मांगें रखी हैं। उन्होंने कहा कि ई10 पेट्रोल के अनुकूल वाहनों के लिए ई10 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। ई20 पेट्रोल की कीमत में 20 प्रतिशत की कमी की जाए। शुद्ध यानी ई0 पेट्रोल, जिसकी मौजूदा खुदरा कीमत उन्होंने 165 से 170 रुपये प्रति लीटर बताई, उसे सस्ता किया जाए। ई20 नीति से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं। वर्ष 2023 से पहले के उन वाहनों के लिए समाधान निकाला जाए, जो ई20 मिश्रित पेट्रोल से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एथेनॉल के मामले में हितों का टकराव है।

हर दूसरे स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था में खामी, निजी स्कूल सबसे ज्यादा फेल; अब तक 1677 स्कूलों की जांच

नई दिल्ली।

दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्कूलों में शुरू हुए निरीक्षण अभियान में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अब तक जांचे गए 1677 स्कूलों में से 774 स्कूलों में सुरक्षा संबंधी गंभीर कमियां मिली हैं। इनमें सबसे अधिक खामियां निजी स्कूलों में पाई गई हैं। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में सभी स्कूलों की जांच पूरी होने तक निरीक्षण के बाद तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं। बाल सुरक्षा माह के तहत 13 जुलाई से शुरू हुए इस विशेष अभियान में राजधानी के सरकारी, सहायता प्राप्त, एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और निजी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जांच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों तथा पॉक्सो कानून के तहत तैयार छात्र सुरक्षा जांच सूची के आधार पर की जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 24 जुलाई तक 1677 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। इनमें 774 स्कूल ऐसे मिले, जहां सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां पाई गईं। इन सभी स्कूलों को निर्धारित समय में कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोबारा निरीक्षण कर यह भी देखा जाएगा कि सुधार वास्तव में हुआ है या नहीं।

सरकारी स्कूलों के 790 परिसरों का निरीक्षण किया गया। इनमें 270 स्कूलों में सुरक्षा संबंधी कमियां मिलीं। वहीं 75 सहायता प्राप्त स्कूलों में से 41 में भी निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता पाया गया। अधिकारियों का कहना है कि सभी श्रेणी के स्कूलों में सुधार की प्रक्रिया एक साथ चल रही है।

निजी स्कूलों की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक

निरीक्षण में सबसे ज्यादा खामियां निजी स्कूलों में सामने आई हैं। जांचे गए 812 निजी स्कूलों में से 463 में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिला। यानी आधे से अधिक निजी स्कूल निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर सके। अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे स्कूलों की निगरानी बढ़ा दी है और सुधार कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है।

रोजाना 150 से 200 स्कूलों का निरीक्षण

निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस, अभिभावकों के प्रतिनिधियों और स्कूल प्रमुखों की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। कई दिनों में 150 से 200 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। अभियान का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द सभी स्कूलों को कवर किया जा सके।

सभी 5633 स्कूलों तक पहुंचेगा अभियान

अधिकारियों के मुताबिक राजधानी के सभी 5633 स्कूलों की जांच पूरी होने तक यह अभियान जारी रहेगा। जिन स्कूलों में कमियां मिली हैं, वहां केवल कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि समयबद्ध सुधार और उसके बाद दोबारा सत्यापन भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य बाल सुरक्षा को केवल एक माह के अभियान तक सीमित रखने के बजाय सभी स्कूलों की स्थायी व्यवस्था का हिस्सा बनाना है।

इन बिंदुओं पर हो रही है जांच

स्कूल में बाल सुरक्षा समिति का गठन हुआ है या नहीं

पॉक्सो कानून के तहत अनिवार्य प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं

शिकायत दर्ज करने और निस्तारण की व्यवस्था

सीसीटीवी कैमरे और उनकी कार्यशील स्थिति

छात्रों की सुरक्षित एंट्री और एग्जिट व्यवस्था

स्कूल स्टाफ का पुलिस सत्यापन

छात्राओं और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण

आपातकालीन सहायता और सुरक्षा प्रोटोकॉल

संवेदनशील मामलों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था

शिक्षकों और कर्मचारियों को बाल सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण।

यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?

नई दिल्ली। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पर रविवार (26 जुलाई) को 4 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ. कीव में भारतीय दूतावास के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, चालक दल के 2 सदस्य सुरक्षित बताए गए हैं, जबकि बाकी 2 के बारे में जानकारी का अभी भी इंतजार है. दूतावास के बयान के मुताबिक यह घटना शनिवार को हुई, जब ओडेसा बंदरगाह पर MV AGN Ragnar पर हमला हुआ. ओडेसा यूक्रेन के अहम ब्लैक सी बंदरगाहों में से एक है, जिस पर 2022 में रूस-यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से कई बार हमले हुए हैं. भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा है कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है. बता दें कि यह घटना ओडेसा बंदरगाह पर रूसी हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत के कुछ दिनों बाद हुई है. यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि जहाज पर मौजूद दो भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं, जबकि अन्य दो भारतीयों के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. दूतावास ने कहा कि वह स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों के संपर्क में है तथा भारतीय नागरिकों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. घटना को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है.

नई पीढ़ी, नया तरीका: न पंजीकृत पार्टी, न जमीनी आधार, फिर भी साथ खड़े हो गए युवा; 36 दिन में की तंत्र की 'सफाई'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच वाली टिप्पणी के विवाद से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) पार्टी ने 36 दिन के आंदोलन में ही शिक्षा मंत्रालय से जुड़े पूरे तंत्र की 'सफाई' कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने कहा कि यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। देश का युवा जाग चुका है। जंतर-मंतर से विरोध प्रदर्शन वापस लेने के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे जरूरी है। युवा देश के भविष्य हैं, वे इसे बहाल करने में सफल रहे हैं। यह बड़ी जीत है। युवाओं ने इस आंदोलन को वापस ले लिया है। दास ने कहा, कृपया उस तरीके को बंद करें, जिससे आप मुस्लिम-विरोधी, ईसाई-विरोधी राजनीति करके शासन करते हैं। कृपया छात्रों सहित हर समुदाय के कल्याण के लिए काम करें, तभी आपको लोगों का भरोसा मिलेगा। युवा इस देश की सभी समस्याओं का समाधान करेगा। यह भी पहला मौका है जब देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने जेन-जी नेताओं के साथ औपचारिक वार्ता की मेज पर बैठकर मांगों पर बिंदुवार फैसले लिए। किसी गैर-राजनीतिक दल का इस तरह सरकार से अपनी शर्तों पर बात करना भी इस आंदोलन का एक असामान्य पहलू रहा। सरकार ने पेपर लीक में जान गवाने वाले बच्चों के परिवारों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने के लिए सैद्धांतिक सहमति जताई है और इसे राष्ट्रीय जवाबदेही माना है।

भावुक हो गईं दीपके की मां कसकर गले लगाऊंगी बेटे को

अभिजीत दीपके के प्रदर्शन से चिंतित उनके माता-पिता आंदोलन खत्म होने से बेहद खुश हैं। मां अनीता दीपके ने कहा, बेटे की चिंता में सो नहीं पा रही थी, पर अब बेहद खुश हूं। बेटे को जल्द घर आने को कहूंगी। नहीं आया, तो हम वापस लाएंगे। मैं उसे कसकर गले लगाऊंगी और आरती उतारूंगी। अभिजीत महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रहते हैं।

न पंजीकृत पार्टी, न जमीनी आधार, फिर भी साथ खड़े हो गए युवा

जेन-जी ने किसी राजनीतिक अनुभव के बिना सिर्फ 36 दिनों में एक केंद्रीय मंत्री की विदाई करा दी। यही नहीं, उनके मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों में भी बड़े पैमाने पर सफाई हुई है।

पहली बार पारंपरिक छात्र संगठनों के बजाय कॉकरोच

जनता पार्टी जैसे एक नए, इंटरनेट-युग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पूरे देशभर में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत नहीं है, फिर भी परीक्षा प्रणाली की खामियों और जवाबदेही जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रभावशाली अभियान चलाकर राष्ट्रीय एजेंडा तय कर दिया। सीजेपी के आंदोलन ने देश के अलग-अलग हिस्सों और विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोगों को एक मंच पर ला खड़ा किया। पूरे मध्य वर्ग, गृहिणियों, डॉक्टरों, वकीलों और अभिभावकों ने बच्चों के भविष्य के लिए सामूहिक सड़क-प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सरकार ने पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें बना दी हैं और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए विधेयक लाने वाली है, जिसमें 10 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल सजा का प्रावधान किया गया है।

सम्पादकीय...

ईरान युद्ध

2024 और 2026 के बीच, मध्य पूर्व एक लंबे छाया युद्ध से सीधे राज्य-से-राज्य संघर्ष में बदल गया। 13 जून, 2025 को इसराईल ने ईरान में परमाणु सुविधाओं पर अचानक और छिपकर हमले किए। अमेरिका ने 22 जून, 2025 को 'मिडनाइट हैमर' नामक ऑपरेशन के तहत इस हमले में भाग लिया, ताकि ईरान की उन परमाणु सुविधाओं को नष्ट किया जा सके, जिन्हें इसराईली हमलों से नष्ट नहीं किया जा सका था। सात बी-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बरों ने व्हिटमैन, मिसूरी स्थित अपने बेस से लगातार 18 घंटे उड़ान भरी और क्रमशः फोर्डो और नतांज स्थित ईरानी परमाणु स्थलों पर बंकर-बस्टिंग बम गिराए। बमबारी से काफी नुकसान हुआ लेकिन इससे ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। तेहरान ने अपने 'एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस' (प्रतिरोध की धुरी) का लाभ उठाकर जवाबी कार्रवाई की, जो मध्य पूर्व में सशस्त्र समूहों और राज्य अभिनेताओं का एक ढीला-ढाला नेटवर्क है। इसे बोलचाल की भाषा में 'शिया क्रिसेंट' भी कहा जाता है, जो इराक पर अमेरिका के अविवेकपूर्ण आक्रमण के बाद उभरा था। इसका सामंजस्य सबसे अच्छी स्थिति में भी अस्पष्ट है। जहां लेबनान में हिजबुल्लाह अपने ईरानी संरक्षक के साथ निकटता से समन्वय करता है, वहीं अन्य, जैसे यमन के हूती, सुविधा के भागीदार है जब उनके हित मेल खाते है। उन्हें जो चीज बांधती है, वे हैं सांझे उद्देश्य-क्षेत्र से अमेरिकी उपस्थिति और प्रभाव को बाहर निकालना, इसराईल का उन्मूलन और फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करना। विच्छेदन से निरंतरता तक : अमेरिका और इसराईल ने फिर से 28 फरवरी, 2026 को, परमाणु प्रश्न पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जिनेवा वार्ता के बीच, क्रमशः 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' नामक अभियान चलाए। यह अभियान ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचे के खिलाफ थे, इस अंतर्निहित धारणा के साथ कि यह दौर ईरानी नेतृत्व को उखाड़ फेंकेगा। यह अंतर्निहित धारणा ईरानी शासन के खिलाफ उन व्यापक विरोध प्रदर्शनों पर आधारित थी जो 28 दिसम्बर, 2025 को शुरू हुए और जनवरी और फरवरी, 2026 के अधिकांश समय तक जारी रहे। तेहरान में मुल्ला शासन द्वारा इन विरोध प्रदर्शनों को बेरहमी से कुचल दिया गया, जिसमें 30,000 से अधिक निहत्थे युवा प्रदर्शनकारी ईरानियों को भारी सैन्य-ग्रेड हथियारों के अंधाधुंध उपयोग द्वारा निर्ममता से मार डाला गया। 1 मार्च, 2026 को, एक अमेरिकी-इसराईली संयुक्त हमले ने अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी, जो 37 वर्षों तक ईरानी सर्वोच्च नेता रहे थे। कुछ ही दिनों के भीतर एक अंतरिम नेतृत्व परिषद का गठन किया गया। मुजतबा खामेनेई ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आई.आर.जी.सी.) के समर्थन से अपने पिता का स्थान लिया। यह हमलों को झेलने की अभूतपूर्व क्षमता ही है जो अब मध्य पूर्व की सुरक्षा वास्तुकला को नया आकार दे रही है। दायित्व के रूप में आधार : मध्य पूर्वी सुरक्षा वास्तुकला अमेरिका की आगे की सैन्य उपस्थिति पर टिकी है, जो 1958 में बेरूत में मरीन लैंडिंग के साथ शुरू हुई थी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार, कुल मिलाकर, अमेरिका के पास मध्य पूर्व में कम से कम 19 देशों में सैन्य सुविधाएं है, जिनमें से 8 को बहरीन, मिस्र, ईराक, इसराईल, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, सीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित देशों में स्थायी माना जाता है। अमेरिकी सेना जिबूती और तुर्की में भी बड़े आधारों का उपयोग करती है, जो अन्य क्षेत्रीय कमानों का हिस्सा है लेकिन अक्सर मध्य पूर्व में अमेरिकी अभियानों में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे ही अमेरिकी और इसराईली सेनाओं ने क्षणिक युद्धविराम के बाद फिर से हमले तेज कर दिए और युद्ध अपने 149वें दिन में प्रवेश कर गया, तेहरान ने पूरे मध्य पूर्व में फिर से हमले शुरू कर दिए, जिससे बहरीन, ईराक, कुवैत, ओमान और कतर के साथ-साथ जॉर्डन और सीरिया को आने वाली मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ रक्षात्मक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तेहरान की कार्रवाई अपने आप में क्षेत्र के वर्तमान सुरक्षा आदेश की रूपरेखा तैयार करती है। ईरान का कहना है कि वह अमेरिकी सुविधाओं पर हमला कर रहा है क्योंकि वाशिंगटन ने अपने क्षेत्रीय आधारों का उपयोग ईरान पर हमलों के लिए लांचपैड के रूप में किया है। एक ऐसा तर्क जो स्वचालित रूप से मेजबान-राज्य के क्षेत्र को एक वास्तविक युद्धक्षेत्र में बदल देता है। 18 जुलाई, 2026 को कुवैत के बिजली, जल और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की कि एक ईरानी हमले ने उसके बिजली उत्पादन और जल विलवणीकरण (डीसैलिनेशन) स्टेशनों में से एक को प्रभावित किया, जिससे आग लग गई और बड़ी संख्या में बिजली उत्पादन इकाइयां सेवा से बाहर हो गईं। एक पुनः अंशांकन (रिकैलिब्रेशन) क्षेत्र : दशकों से, मध्य पूर्व में क्षेत्रीय सुरक्षा इस धारणा पर टिकी थी कि अमेरिकी आधार हमले को रोकते है और खाड़ी देश अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं। ईरान के साथ अमेरिका-इसराईल युद्ध ने दोनों धारणाओं का परीक्षण किया है। अंततः, वर्तमान परिस्थितियों ने स्थायी रूप से इस भ्रम को तोड़ दिया है कि क्षेत्रीय स्थिरता बाहरी संरक्षक को आऊटसोर्स की जा सकती है, जिससे मध्य पूर्व के शक्ति संतुलन का गहरा पुनः अंशांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मध्य-पूर्व राज्यों की गंभीर कमजोरियों को उजागर करके, इस संघर्ष ने साबित कर दिया कि विश्वसनीय निवारण के बिना निष्क्रिय तटस्थता आक्रामकता को रोकने के बजाय उसे आमंत्रित करती है। इस नई भू-राजनीतिक वास्तविकता में जीवित रहने के लिए, मध्य-पूर्व के राज्यों को तेजी से सांझेदारी बहुलवाद की ओर बढ़ना और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में निवेश करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगला सुरक्षा आदेश सामूहिक शक्ति की स्थिति से बातचीत किया जाए, संप्रभु धन को लचीले रणनीतिक बुनियादी ढांचे में बदलना चाहिए।

ताज महल से जुड़ा कानूनी विवाद क्या है?

अब तक की कहानी : 17वीं शताब्दी का मकबरा, ताज महल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस महीने की शुरुआत में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केंद्र और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को नोटिस जारी कर आगरा की एक निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उनका जवाब मांगा था, जिसमें ताज महल के सर्वेक्षण से इंकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने अधिवक्ता हरिशंकर जैन द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें तर्क दिया गया था कि ताज, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है, वास्तव में 'तेजो महालय' है। जैन ने यह घोषणा करने की मांग की कि ताज महल एक हिंदू मंदिर है और हिंदुओं के लिए वहां पूजा-अर्चना करने की अनुमति मांगी। याचिकाकर्ताओं ने स्मारक का निरीक्षण करने के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की भी मांग की। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी अर्जुमंद बानो के मकबरे के रूप में निर्मित, ताज महल को पूरा होने में 22 साल लगे। मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में निर्मित, पहली बार इसे विवाद का सामना तब करना पड़ा, जब पश्चिम में कई लोगों द्वारा यह दावा किया गया कि ताज के वास्तुकार वेनेशियन गेरोनिमो वेरोनियो थे, जो पेशे से एक जौहरी थे। वह 17वीं शताब्दी की बात थी। फिर तारीख-ए-ताज महल में मुगल बेग का दावा आया कि ताज को तुर्की के सुल्तान द्वारा कथित रूप से भेजे गए एक वास्तुकार मुहम्मद एफेंडी ने डिजाइन किया था। हालांकि, एफेंडी वास्तुकार नहीं थे, जैसा कि बाद के खुलासों से साबित हुआ। पी.एन. ओक का दावा क्या था : फिर 19वीं शताब्दी के मध्य में, यह दावा किया गया कि यह स्मारक फ्रांसीसी ऑस्टिन डी बोर्डो की प्रतिभा का परिणाम था, जो पेशे से एक जौहरी थे।

हालांकि, ऑस्टिन की मृत्यु 1632 में हो गई, जिस वर्ष ताज पर काम शुरू हुआ था।मध्यकालीन भारत के किसी भी इतिहासकार ने ताज के मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी का मकबरा होने के तथ्य का खंडन नहीं किया है। इसमें इरफान हबीब और अतहर अली जैसे प्रख्यात इतिहासकारों के अलावा सतीश चोपड़ा और सैयद अली नदीम रजावी जैसे उल्लेखनीय नाम शामिल हैं। मकबरे की प्रामाणिकता पर आक्षेप लगाने वाले पहले व्यक्ति एक गैर-इतिहासकार, पी.एन. ओक थे, जो एक शिक्षक से वकील और फिर पत्रकार बने थे, जिन्होंने 1965 में अपनी पुस्तक 'ताज महल इज ए टैम्पल पैलेस' के माध्यम से दावा किया था कि ताज मूल रूप से 4वीं शताब्दी में निर्मित एक राजपूत महल था। 1989 में, ओक ने अपनी राय को संशोधित किया और दावा किया कि यह मूल रूप से 12वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक इस्लाहू मंदिर था। फिर से, उन्होंने अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए एक पुस्तक, 'ताज महल : द ट्रू स्टोरी' लिखी। यह पहली बार था, जब किसी ने इस स्मारक को किसी हिंदू देवता से जोड़ा था। साक्ष्यों के अभाव में इतिहासकारों ने उनके दावों को साख के लायक न मानते हुए खारिज कर दिया। ओक का दावा, हालांकि, उच्चतम न्यायालय में सुना गया था, जिसने इसे 2000 में सिरे से खारिज कर दिया था। फिर कौन सी कानूनी चुनौतियां आईं : 2005 में, अयोध्या सद्भावना समिति के सदस्य अमरनाथ मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए और दावा किया कि ताज 1189 में चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया एक मंदिर था। अदालत ने उनके तर्क को भी खारिज कर दिया। विरोधियों ने हार नहीं मानी। 2015 में, आगरा की एक निचली अदालत में दायर एक सिविल मुकदमे में ताज महल को हिंदू मंदिर घोषित करने की मांग की गई। अदालत हालांकि इस दावे से सहमत नहीं हुई। ताज परिसर के सर्वेक्षण का आदेश देने से इंकार करने के बाद, जैसा कि ज्ञानवापी और भोजशाला में आदेश दिया गया था, याचिकाकर्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंचे। इसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार और ए.एस.आई. से जवाब मांगा। ए.एस.आई. का क्या रुख था : 2017 में, ए.एस.आई. ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ताज 17वीं शताब्दी का मकबरा था। इसके निर्माण और डिजाइन में इस्तेमाल की गई तकनीक, जिसमें 'पित्रा दुरा' शामिल है, पूर्व-मध्यकालीन दिनों में मौजूद नहीं थी। इस विवाद के किसी भी अवशेष को समाप्त कर देना चाहिए था। हालांकि, 2022 में उच्चतम न्यायालय में एक भाजपा नेता द्वारा एक जनहित याचिका (पी.आई.एल.) दायर की गई थी। इसे भी खारिज कर दिया गया। 2 साल बाद, कुछ कार्यकर्ताओं ने ताज में गंगाजल चढ़ाने की कोशिश की। यह प्रयास भी नाकाम कर दिया गया। अब, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, गेंद एक बार फिर ए.एस.आई. के साथ-साथ केंद्र के पाले में है।

'दल-बदली' असल में लोकतंत्र का खंडन

'दल -बदल' हकीकत में लोकतंत्र का खंडन है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत 'जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा' है। जबकि दल-बदल संबंधित 'दल-बदलू' द्वारा जनादेश के साथ किया गया विश्वासघात है। 'दल-बदलू' कभी भी 'जनता का और जनता के लिए' वाली भूमिका अदा नहीं कर सकता। वह अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए भविष्य में भी जनता से मिले समर्थन से दगा कमाएगा, या फिर राजनीति के खेल में दगा कमाने वाली शक्तियों की कठपुतली के रूप में हस्तक्षेप करेगा। अवसरवादी राजनीतिक नेताओं द्वारा आजकल की जा रही विशुद्ध रूप से स्वार्थी हितों से प्रेरित, सिद्धांतहीन दल-बदलियों के प्रति आम जनता की प्रतिक्रिया को भी उपर्युक्त अनुभवों की रोशनी में ही मापा जा सकता है। 'दल-बदल' का कारण, जन-हितैषी विचारधारा के प्रति समर्पित होकर जनता की भलाई के लिए राजनीतिक रणक्षेत्र में कूदना, जैसा कि नेता पार्टी बदलते समय अक्सर बयानबाजी करते है, बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि इस निंदनीय प्रवृति का मुख्य कारण तो राजनीति को सत्ता का आनंद लेने और मनमर्जी से लूट-खसोट करने का साधन समझना है। 2014 में, मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय सत्ता हथिया लेने के बाद 'दल-बदल' कराने के लिए भाजपा द्वारा साम-दाम-दंड-भेद की गंदी नीति के तहत हर ओछा हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे ये दल-बदल सत्ता और धन के लोभ-लालच के तहत और भ्रष्टाचार करने के एवज में मिलने वाली सजा से बचने के लिए किए जा रहे है। आर.एस.एस. और इससे जुड़े संगठनों ने ई.डी., सी.बी.आई. आदि एजेंसियों द्वारा की जाने वाली संभावित कार्रवाइयों के जरिए दूसरे राजनीतिक दलों के भ्रष्ट और चरित्रहीन नेताओं को डराकर दल-बदल करवाने को एक 'लाभदायक धंधा' बना लिया है। इस काम में सरकारी व गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट घराने और भगवा विचारों से प्रभावित नौकरशाह भी संघ-भाजपा का पूरा हाथ बंटा रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में नैतिकता, सिद्धांतवादिता और स्वाभिमान की भावना से अछूतेपन के कारण आम लोग भी राजनीति में आई विकृतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। उल्टा, कई बार तो किसी न किसी लालच के वशीभूत होकर वे स्वार्थी 'दल-बदलुओं' का साथ देने में भी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। 'दल-बदल विरोधी कानून' भी शासक वर्गों के नियंत्रण में होने के कारण 'दल-बदल' की इस घातक बीमारी को रोकने में सक्षम नहीं रहा। अब उम्मीद सिर्फ आम लोगों की पैनी और उच्च राजनीतिक-विचारधारात्मक चेतना पर ही रखी जा सकती है। लोगों को जागरूक करके ही दल-बदलुओं को जनता से अलग-थलग करने की आशा की जा सकती है। दल-बदल, चाहे किसी भी दल के किसी भी बड़े या छोटे नेता द्वारा किया जाए, लोगों को चाहिए कि वे ऐसे खोटे इंसान का हर क्षेत्र में पूर्ण बहिष्कार करके उसे 'बेइज्जत' करें। यदि किसी राजनेता का अपनी वर्तमान पार्टी की नीतियों या विचारधारा से कोई मतभेद खड़ा हो गया है या उसे किसी अन्य विचारधारा से लगाव हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति पहले वे सभी पद त्यागे, जो आम जनता द्वारा उसे उस पार्टी में रहते हुए बख्शे गए थे। साथ ही नई पार्टी में उसे निचले स्तर पर काम दिया जाए ताकि वह नई विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित कर सके। संभव है कई लोग इस प्रक्रिया को असंभव या व्यावहारिक न होने योग्य कहकर इसकी निंदा करें।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन: अस्तित्व पर मंडराता खतरा

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है। इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते है। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में है।

अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके है और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है।

दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही है जहां जल संसाधन सीमित है। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया। जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी है। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है।

भारत में कभी तालाब, बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रिंकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसी कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करें। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा।

इसलिए जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि 'जल बचाना ही भविष्य बचाना है।' हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। वर्षा की प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है।

बिट्टू की एंट्री से बदली पंजाब की चुनावी बिसात, नया समीकरण गढ़ने में भाजपा कामयाब

केंद्रीय मंत्री पद से रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा पंजाब की राजनीति में भाजपा के सबसे बड़े चुनावी दांव के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बिट्टू विधानसभा चुनाव लड़ सकते है और पार्टी के चुनाव अभियान का प्रमुख चेहरा भी बन सकते है। उल्लेखनीय है कि रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो चुका था। इसके बाद उन्होंने रेल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। बिट्टू ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें देश और विशेष रूप से पंजाब की सेवा करने का अवसर मिला तथा उनका सार्वजनिक जीवन राष्ट्रवाद, सेवा और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे भी जारी रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र बिट्टू लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। वर्ष 2009 में वह आनंदपुर साहिब से सांसद बने और बाद में दो बार लुधियाना का प्रतिनिधित्व किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थामा, लेकिन लुधियाना से कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पंजाब की राजनीति में बिट्टू की वापसी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि वह पिछले कुछ समय से पंजाब में भाजपा के संगठन और चुनावी तैयारी में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि भाजपा का लक्ष्य पंजाब में 'डबल इंजन सरकार' बनाना है और प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना है। दरअसल, बिट्टू की वापसी भाजपा की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत पार्टी पंजाब में अपने पारंपरिक शहरी हिंदू वोट बैंक से आगे बढ़कर सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच भी मजबूत आधार तैयार करना चाहती है। पंजाब में लगभग 58 प्रतिशत आबादी सिखों की है, जबकि करीब 39 प्रतिशत हिंदू है। इसके अलावा राज्य में लगभग 32 प्रतिशत दलित और लगभग 16 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग है। भाजपा की कोशिश इन चारों सामाजिक वर्गों में समानांतर स्वीकार्यता बढ़ाने की है। भाजपा की इसी नई रणनीति की झलक हाल में आई 'सतलुज' फिल्म को लेकर हुए विवाद में भी देखने को मिली थी। रवनीत सिंह बिट्टू ने फिल्म का खुलकर विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह ऐसे संवेदनशील विषय को उभारने का प्रयास है, जिससे पंजाब का माहौल दोबारा तनावपूर्ण हो सकता है। उन्होंने इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली कोशिश बताते हुए फिल्म पर सवाल उठाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिट्टू का यह रुख भाजपा की बदली हुई चुनावी रणनीति का संकेत था। पहले जहां पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर अपेक्षाकृत आक्रामक भाषा का प्रयोग करती थी, वहीं अब वह सिख समुदाय की धार्मिक और ऐतिहासिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति को अधिक संतुलित और संयमित बना रही है। माना जा रहा है कि भाजपा पंजाब में सिख मतदाताओं के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों पर सावधानीपूर्वक राजनीतिक संदेश देना चाहती है, ताकि हिंदू, सिख, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन चारों प्रमुख सामाजिक समूहों में समानांतर स्वीकार्यता विकसित की जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने स्वतंत्र राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में लगातार काम किया है। इसका असर चुनावी आंकड़ों में भी दिखा, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में लगभग 6.6 प्रतिशत मत पाने वाली भाजपा का वोट प्रतिशत 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर लगभग 19 प्रतिशत तक पहुंच गया। यही कारण है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले दम पर सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के साथ भाजपा के रिश्तों को लेकर राजनीतिक अटकलें अब भी खत्म नहीं हुई है। इसका ताजा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान देखने को मिला था। जालंधर की सभा में प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और 'अकाली दल' तीनों पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल भी आपसी स्वार्थों के कारण पंजाब की प्रभावी सेवा नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने किसी विशेष अकाली गुट का नाम नहीं लिया, लेकिन शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बाद में दावा किया कि यह टिप्पणी उनकी पार्टी पर नहीं, बल्कि अन्य अकाली धड़ों के लिए थी। इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी, क्योंकि भाजपा और अकाली दल का लगभग 25 वर्षों पुराना गठबंधन 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर टूटने के बाद भी दोनों दलों के हर सार्वजनिक बयान को संभावित राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। हालांकि भाजपा नेतृत्व फिलहाल गठबंधन पुनर्जीवित करने की किसी संभावना से इंकार कर रहा है और अपने संगठन को स्वतंत्र रूप से मजबूत करने की बात कह रहा है, फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब की राजनीति में भाजपा और अकाली दल के संबंध इतने महत्वपूर्ण रहे है कि दोनों दलों के बीच होने वाला हर संवाद भविष्य की संभावनाओं के नजरिए से परखा जाता है। साथ ही भाजपा ने अपने राजनीतिक संदेश और भाषा में भी उल्लेखनीय बदलाव किया है। कभी ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाने वाली पार्टी अब सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक शिकायतों को अधिक संवेदनशीलता से संबोधित करती दिखाई दे रही है। पार्टी लगातार कांग्रेस को ऑपरेशन ब्लू स्टार, पंजाब में आतंकवाद के दौर और 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए जिम्मेदार ठहराती है, जबकि स्वयं को सिख समाज की भावनाओं का सम्मान करने वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। देखा जाये तो भाजपा की इस बदली हुई राजनीतिक रणनीति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए उसके पुराने रुख पर भी नजर डालना जरूरी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी आत्मकथा 'माय कंट्री, माय लाइफ' में पंजाब में उग्रवाद के दौर के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उग्रवाद को बढ़ावा दिया और हालात इतने बिगड़ने दिए कि अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार की नौबत आ गई। आडवाणी ने यह भी लिखा था कि भाजपा और अन्य दलों के देशव्यापी आंदोलनों के दबाव में तत्कालीन केंद्र सरकार को स्वर्ण मंदिर परिसर से उग्रवादियों को हटाने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि अब पंजाब में चुनावी विस्तार की कोशिशों के बीच भाजपा की सार्वजनिक भाषा पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित और संवेदनशील दिखाई देती है। पार्टी अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को 'राष्ट्रीय त्रासदी' बताते हुए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन साथ ही सिख समाज की धार्मिक भावनाओं और ऐतिहासिक पीड़ा को भी प्रमुखता से स्वीकार करने का प्रयास कर रही है। इसी बदलाव के तहत भाजपा ने हाल के वर्षों में कई प्रतीकात्मक और राजनीतिक कदम उठाए है। वीर बाल दिवस की घोषणा, करतारपुर साहिब गलियारे का उद्घाटन, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप भारत लाना, 1984 दंगों के मामलों की जांच में तेजी, हवाई अड्डों पर कृपाण ले जाने की अनुमति, स्वर्ण मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे तथा लंबे समय से जेल में बंद कुछ सिख कैदियों को मानवीय आधार पर राहत जैसे फैसलों को इसी व्यापक सिख पहुंच अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा ने यह भी संकेत दिया है कि सत्ता में आने पर धर्मांतरण विरोधी कानून लाया जा सकता है। हालांकि भाजपा इस पूरे अभियान के दौरान एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भारती ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पॉकेट्स्थल एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भारती, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/40863)

हिंदी साहित्य सम्मान का नाम बदलना साहित्यिक विरासत पर आघात –साहित्यकारों, पत्रकारों और चिंतकों में रोष

नई दिल्ली।(आकाश शक्य) दिल्ली सरकार द्वारा हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित सम्मान का नाम बदलकर 'वीर सावरकर साहित्य सम्मान' किए जाने के निर्णय को लेकर साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक जगत में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अनेक साहित्यकारों, वरिष्ठ पत्रकारों और सामाजिक चिंतकों ने इस कदम को हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा और उसकी स्वतंत्र पहचान पर आघात बताया है।

वरिष्ठ पत्रकार उमेश जोशी ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, –यह सम्मान की असीम गरिमा को सीमित दायरे में समेटने जैसा है। साहित्य और संस्कृति के नाम पर राजनीतिक विचारधारा थोपी जा रही है। साहित्यिक संस्थाओं और सम्मानों की गरिमा को राजनीतिक विचारधाराओं की भेंट चढ़ाया जा रहा है।–

राष्ट्रीय विचारक एवं वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा, –साहित्य किसी सत्ता, दल या विचारधारा की जागीर नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत दस्तावेज होता है। साहित्यिक सम्मानों की पहचान बदलना केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि उस विरासत और परंपरा को कमजोर करने का प्रयास है जिसे पीढ़ियों के साहित्यकारों ने अपने श्रम, चिंतन और सृजन से निर्मित किया है। इतिहास को सम्मान दीजिए, लेकिन साहित्य को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए।

चतुर्वेदी ने आगे कहा कि –जब सरकारें साहित्यिक संस्थाओं की स्वायत्तता और ऐतिहासिक पहचान में हस्तक्षेप करती हैं, तब यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं रह जाता, बल्कि सांस्कृतिक विमर्श और बौद्धिक स्वतंत्रता का विषय बन जाता है।

गांधीवादी नेता रमेश चंद शर्मा ने कहा कि साहित्य समाज को जोड़ने और मानवीय मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने इस निर्णय को सांस्कृतिक विरासत के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि साहित्यिक पुरस्कारों की ऐतिहासिक पहचान को समाप्त करना उचित नहीं है।

महान चिंतक एवं विचारक बी.आर. चौहान ने भी इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, –साहित्य समाज की आत्मा है। इसे राजनीतिक आग्रहों और वैचारिक प्रतिस्पर्धाओं का माध्यम बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों और बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती है।

साहित्यिक और सांस्कृतिक जगत के अनेक प्रतिनिधियों ने इस निर्णय को –सांस्कृतिक विरासत पर प्रहार–, साहित्य के राजनीतिकरण का प्रयास– और –बौद्धिक स्वतंत्रता के लिए खतरा– बताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि साहित्य समाज को जोड़ने का कार्य करता है और उससे जुड़े निर्णय व्यापक संवाद, संवेदनशीलता और सहमति के आधार पर लिए जाने चाहिए।

लाला राम चरण अग्रवाल की 50वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजित

नई दिल्ली।(इंद्रजीत सिंह) स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा, महान समाजसेवी, राष्ट्र निर्माण के कर्मठ सेनानी तथा दिल्ली नगर निगम के प्रथम उपमहापौर स्वर्गीय लाला राम चरण अग्रवाल की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजधानी दिल्ली में एक गरिमामयी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बहादुरशाह ज़फर मार्ग स्थित उनकी भव्य प्रतिमा स्थल पर आयोजित इस कार्यक्रम में राजनीति, प्रशासन, समाज सेवा एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए।

कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सविता शर्मा, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.वी. श्रीनिवास, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद श्री जय प्रकाश अग्रवाल, पूर्व सांसद डॉ. उदित राज, दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री श्री मंगतराम सिंघल सहित अनेक विशिष्ट अतिथियों ने लाला राम चरण अग्रवाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

स्वर्गीय लाला राम चरण अग्रवाल के परिवार की ओर से श्री आत्मप्रकाश अग्रवाल, श्री मुदित अग्रवाल एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्र टाइम्स के प्रधान संपादक एवं एक्रिडिटेड जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजय शंकर चतुर्वेदी ने भी लाला जी के योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

सभा में पूर्व विधायक विपिन शर्मा, शादी राम, पूर्व पार्षद जितेंद्र सिंह कोचर, शरणजीत शर्मा, अनिल शर्मा, सुखबीर शर्मा, एस.के. पुरी, अमित त्यागी, नरेश शर्मा 'नीटू', राजेश प्रजापति, मोहम्मद ताहिर, पूर्व एल्डरमैन आर.बी. सिंह, प्रदीप गुप्ता, राकेश कुमार, निगम पार्षद किरण वाला, सतीश सैनी, मनोज गुप्ता, एल्डरमैन सत्येंद्र शर्मा, मुरारी लाल, राजेश गर्ग, विनय नाहटा, पराग जैन सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अपने संबोधन में श्रीमती सविता शर्मा ने कहा, –लाला राम चरण अग्रवाल स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली परंपरा के प्रतीक थे। उनका जीवन देश के लिए संघर्ष, समाज के लिए सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पण का आदर्श उदाहरण रहा। उन्होंने न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्र भारत में भी सामाजिक न्याय और गरीबों के उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया।– अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.वी. श्रीनिवास ने कहा, –लाला राम चरण अग्रवाल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि विचारों के योद्धा थे। उन्होंने जिस सादगी, ईमानदारी और सेवा भावना से जीवन जिया, वह आज के नेताओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज निर्माण में योगदान देना चाहिए।– पूर्व सांसद डॉ. उदित राज ने कहा, –देश को आजादी दिलाने के बाद लाला जी ने समाज के वंचित एवं हाशिए पर खड़े लोगों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। दिल्ली में रैनबसेरों की शुरुआत कर उन्होंने हजारों जरूरतमंदों को आश्रय प्रदान करने की व्यवस्था की। उनका जीवन सामाजिक समरसता और मानव सेवा की मिसाल है।– वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा, –मुझे लाला राम चरण जी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। उनके व्यक्तित्व, अनुशासन, सेवा भावना और जनसमर्पण से मैंने बहुत कुछ सीखा। सार्वजनिक जीवन में जो भी प्रेरणा मुझे मिली है, उसमें लाला जी का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसे महान व्यक्तित्वों के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।– वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाला राम चरण अग्रवाल ने कई बार जेल यात्राएं कीं, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने सामाजिक सरोकारों को अपना मिशन बनाया और दिल्ली नगर निगम के प्रथम उपमहापौर के रूप में जनहित को प्रशासन का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दिल्ली में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अनेक जनकल्याणकारी कार्यों की नींव रखी, जिनका लाभ आज भी समाज के विभिन्न वर्गों को मिल रहा है।श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि लाला राम चरण अग्रवाल जैसे महापुरुष इतिहास की अमूल्य धरोहर होते हैं और उनके आदर्शों, विचारों तथा स्मृतियों को जीवंत रखना आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने सैकड़ों उपस्थित नागरिकों, वरिष्ठ समाजसेवियों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों को शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। श्रद्धांजलि सभा का समापन राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और जनसेवा के प्रति समर्पण के संकल्प के साथ हुआ। उपस्थित लोगों ने लाला राम चरण अग्रवाल के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने तथा उनकी स्मृति को सदैव जीवित रखने का संकल्प व्यक्त किया।

नाईवाड़ा में पेयजल लाइन में सीवर का पानी मिलने से लोग परेशान, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई

नई दिल्ली। (ए.के.चौधरी)पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार स्थित नाईवाड़ा क्षेत्र के निवासी एवं प्रख्यात फोटोग्राफर तथा वरिष्ठ नागरिक श्री अशोक निगम ने क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सीवर का पानी मिलने की गंभीर समस्या को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अशोक निगम, निवासी 2511, नाईवाड़ा, चावड़ी बाजार, ने बताया कि उनके घर सहित आसपास के अनेक मकानों में पिछले कई दिनों से नलों के माध्यम से कीचड़युक्त एवं दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। उनका कहना है कि क्षेत्र में सीवर पाइपलाइन टूट जाने के कारण सीवर का गंदा पानी पेयजल लाइन में मिल रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में सीवर विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन विभाग की ओर से अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, किंतु वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

स्थानीय निवासियों का आरोप है कि टूटी हुई सीवर लाइन के कारण घरों में आने वाला पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। लोगों को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों को आशंका है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जलजनित बीमारियों का प्रकोप फैल सकता है।

नाईवाड़ा के निवासियों ने दिल्ली जल बोर्ड, सीवर विभाग तथा दिल्ली सरकार से मांग की है कि मामले की तत्काल जांच कर क्षतिग्रस्त सीवर पाइपलाइन की मरम्मत कराई जाए तथा प्रभावित क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे जनहित में व्यापक आंदोलन करने को विवश होंगे।

स्थानीय लोगों ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके।

विधायक पी.एन. पाठक व नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी प्रधानमंत्री के 'मन की बात'

कुशीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' का 136वां एपिसोड रविवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक रूप से सुना गया। कसया नगर के बूथ संख्या 326 पर विधायक पी.एन. पाठक ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम सुना, जबकि पडरौना नगरपालिका परिषद के बूथ संख्या 250 पर नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कसया में विधायक पी.एन. पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं तथा भारत विश्व में अपनी सशक्त पहचान बना रहा है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने और समाजहित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष आद्या पाण्डेय, डॉ. छेदी शर्मा, राज पाठक, राजन जायसवाल, कुश मद्धेशिया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद पडरौना में आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि कृषि, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, खेल और अंतरिक्ष सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

उन्होंने प्रधानमंत्री के जल संरक्षण, युवा शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष 'बुलबुल' जायसवाल, बूथ अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, राजेश कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

15 अगस्त तक दिल्ली में रहेंगी सीआरपीएफ-आरएएफ की 83 कंपनियां, 50 के अलावा 33 और बटालियन होंगी तैनात

नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' और इसकी विशेष इकाई 'आरएएफ', की 83 कंपनियां दिल्ली में तैनात रहेंगी। यह 15 अगस्त तक की गई है। सीआरपीएफ की तैनाती में तीन महिला कंपनी भी होंगी। फिलहाल दिल्ली में सीआरपीएफ की 50 कंपनियां मौजूद हैं। ये कंपनियां दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगी। बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की मांग पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अर्धसैनिक बलों की 45 कंपनियों को तैनात करने की मंजूरी दी थी। इन 45 कंपनियों को 27 जुलाई तक दिल्ली में तैनात रहने का आदेश दिया गया था। प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ की 24, आरएएफ 15, बीएसएफ 3, आईटीबीपी 1 और एसएसबी की 2 कंपनियां दिल्ली में तैनात की गई थीं। कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया। शुक्रवार को सुरक्षा कारणों के चलते सीआरपीएफ की अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात करने का आदेश जारी किया गया। इनमें 16 कंपनियां, हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची थी, जिसमें दस कंपनी सीआरपीएफ और छह कंपनी आरएएफ की हैं। सीएपीएफ की इन कंपनियों से कहा गया है कि वे सभी प्रकार के अत्याधुनिक दंगा रोधी उपकरणों, ओपी स्केल आर्म्स व गोला बारूद से लैस रहें। दिल्ली में आरएएफ की 15 कंपनियों और सीआरपीएफ की 24 कंपनियों को पहले 27 जुलाई तक तैनात किया गया था। अब अतिरिक्त 26 कंपनियां दिल्ली पहुंच रही हैं। इनमें तीन महिला कंपनी भी शामिल हैं। पहले से मौजूद आरएएफ की 6 कंपनियों को 16 अगस्त तक दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया गया है। आरएफ की अतिरिक्त 12 कंपनियां, जो देर सवेर दिल्ली में पहुंच जाएंगी, वे भी 16 अगस्त तक यहीं पर रहेंगी।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन खत्म, एनडीएमसी ने रातभर में हटाया 60 मीट्रिक टन कचरा

नई दिल्ली। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन समाप्त होने के तुरंत बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने पूरे क्षेत्र में विशेष स्वच्छता, मरम्मत और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया। रातभर चले इस अभियान में लगभग 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। एनडीएमसी के अनुसार, अभियान में 500 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल स्वयं पूरी रात मौके पर मौजूद रहे और अभियान की निगरानी करते हुए अधिकारियों को कार्य शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। रविवार दोपहर चहल ने जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्रों का दोबारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन समाप्त होते ही एनडीएमसी की टीमें तत्काल मैदान में उतर गई थीं, ताकि राजधानी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जनजीवन और यातायात जल्द सामान्य हो सके। अभियान के तहत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सिविल इंजीनियरिंग तथा उद्यान विभाग ने संयुक्त रूप से कार्य किया। जंतर-मंतर के अलावा टॉलस्टॉय रोड, संसद मार्ग, जयसिंह रोड, जनपथ और कनॉट प्लेस के आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, फुटपाथों, डिवाइडरों, हरित पट्टियों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, धुलाई, मरम्मत और पुनर्स्थापन किया गया। सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने करीब 50 कर्मचारियों को तैनात किया। चार जेटिंग मशीनों से सड़कों और फुटपाथों की धुलाई कराई गई। दीवारों पर लिखे नारों को हटाकर दोबारा रंगाई-पुताई की गई, जबकि क्षतिग्रस्त कर्ब स्टोन और फुटपाथों की मरम्मत भी कराई गई। वहीं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग की ओर से रात में 75 और सुबह 35 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाया गया। आठ ऑटो टिपर, दो भारी ट्रक, एक जेसीबी और तीन हाई-प्रेशर जेटिंग मशीनों की मदद से पूरे क्षेत्र से करीब 60 मीट्रिक टन कचरा हटाया गया। उद्यान विभाग ने हरित पट्टियों और डिवाइडरों की सफाई के साथ पौधों एवं उद्यान क्षेत्रों का पुनर्स्थापन भी किया। चहल ने कहा कि एनडीएमसी की प्राथमिकता प्रदर्शन के बाद सार्वजनिक स्थलों को कम से कम समय में स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। उन्होंने दावा किया कि परिषद ने पूरे प्रदर्शन स्थल की सफाई किसी भी अन्य प्रतीकात्मक सफाई गतिविधि से पहले पूरी कर ली थी। उन्होंने पूरी रात कार्यरत अधिकारियों, अभियंताओं, सफाई कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ की सराहना करते हुए कहा कि एनडीएमसी के कर्मचारी परिषद की सबसे बड़ी ताकत हैं। साथ ही नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में सहयोग करने की अपील भी की।

दिल्ली के हौज खास में कपड़ा दुकानदार की गला घोंटकर हत्या, भीड़ ने आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंपा

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाना क्षेत्र में एक कपड़ा दुकानदार की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर हौज खास में ही अपने रूम पर लौट रहा था। पीछे से आकर हमलावर ने बेल्ट से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी को भीड़ ने मौके से ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक की पहचान नवादा जिला (बिहार) के माई गांव निवासी 49 वर्षीय मनोज सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, तैमूर नगर निवासी आरोपी लोकेश को मौके से ही पकड़ लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच के मुताबिक, बस स्टैंड पर हुई मामूली कहासुनी मारपीट में बदल गई थी। बिट्टू कुमार के मुताबिक, घटना बृहस्पतिवार रात की है। उनके पिता सफदरजंग अस्पताल के गेट नंबर दो के पास पिछले 25 वर्ष से कपड़े की दुकान लगा रहे थे। घटना वाली रात 10 बजे दुकान बंद करके वे रूम पर लौट रहे थे। इतने में नशे में धुत शराबी ने जानबूझकर उन्हें धक्का दिया और झगड़ा करने लगा। वे झगड़ा बचाकर वहां से जाने लगे तो आरोपी ने अपना बेल्ट निकाल लिया और पीछे से आकर गले में डालकर कस दिया। दम घुटने से वे अचेत होकर गिर पड़े। बताया कि आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी । पुलिस ने अचेत हालत में पिता को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बिट्टू कुमार गुरुग्राम के चक्करपुर में रहकर प्राइवेट जॉब करते हैं। उनकी चार बहनें हैं। उन्होंने रेखा गुप्ता सरकार से विनती करते हुए कहा कि दिल्ली-एनसीआर में रोजगार के लिए आने वालों को सुरक्षा दी जाए। जो भी व्यक्ति गलत करता है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

दक्षिणी राज्यों में कोरोना का बढ़ता खतरा, अस्पतालों ने तैयार किए इमरजेंसी बेड; फिर आ रही महामारी?

नई दिल्ली । साल 2020-23 के कोरोना के दौर की डरावनी यादें शायद ही कोई भूल पाया होगा। कोरोना की आई तीन लहरों के दौरान अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, ऑक्सीजन की कमी, मास्क और सेनिटाइजर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। हालांकि इसके बाद हालात काफी सामान्य हो गए और हम सभी मानने लगे थे कि अब खतरा टल गया है। हालांकि कोरोना वायरस एक बार फिर से दस्तक देता दिख रहा है। पिछले करीब एक महीने से देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, केरल, आंध्र-प्रदेश और तेलंगाना से संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की खबरें सामने आती रही हैं। हाल के रिपोर्ट्स में देश के दक्षिणी राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कोविड-19 के मामलों में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी भले ही महामारी के दौर जैसी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे नजरअंदाज करने की गलती न करने की सलाह दे रहे हैं। राज्य सरकारों ने निगरानी बढ़ा दी है, अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा गया है और संदिग्ध मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। प्रकाशित एक रिपोर्ट में हमने बताया था कि इस बार बढ़ते मामलों के लिए मुख्यरूप से ओमिक्रॉन के JN.5 सब-वेरिएंट को कारण माना जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में संक्रमण के करीब 50 मामले

आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार संक्रमण के मामलों में वृद्धि की खबरें सामने आती रही हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार (25 जुलाई) को राज्य में कोविड-19 के 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से चार लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल, 24 मरीज अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, जबकि 16 मरीज मेडिकल देख-रेख में घर पर ठीक हो रहे हैं। अब तक, पांच लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वी गोदावरी जिले में सबसे ज्यादा 11 मामले दर्ज किए गए हैं। गुंटूर में नौ मामले दर्ज किए गए, इसके बाद कडप्पा में आठ, विशाखापत्तनम में पांच, एनटीआर में तीन और काकीनाडा, एलुरु और बापटला में दो-दो मामले सामने आए।

तेलंगाना में भी अलर्ट

तेलंगाना में भी कोरोना के मामलों को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ और परिवार कल्याण निदेशक डॉ. बी. रविंदर नायक ने शुक्रवार को बताया था कि कोविड-19 के मामलों में अभी जो बढ़ोतरी दिख रही है, वह हल्की है और पिछले साल इसी समय देखे गए ट्रेंड जैसी ही है। इसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ बुजुर्गों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां भीड़-भाड़ ज्यादा हो। संक्रमण से बचाव के ये उपाय सांस की अन्य बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं, क्योंकि इस समय मौसमी इन्फ्लूएंजा के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार निगरानी बनाए हुए हैं।

अस्पतालों को किया गया है अलर्ट

मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभावित शहरों में अस्पतालों में अलर्ट किया गया है।

मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल

मीराबाई चानू की स्वर्णिम हैट्रिक: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय भारोत्तोलक का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, छलके आंसू

ग्लासगो । भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने महिला 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का यह कुल तीसरा और पहला स्वर्ण पदक है। चानू ने स्नैच में 85 किलो और क्लीन एंड जर्क में 105 किलो का वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 190 किलो वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता। चानू ने इससे पहले 2018 और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। मीराबाई के अलावा नाइजीरिया की रुथ असुक्वो नियोग ने 168 किलो के साथ रजत और मलयेशिया की इरेने जाने हेनरी ने 167 किलो वजन के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

स्नैच में तोड़ा रिकॉर्ड

मीराबाई चानू ने स्नैच के तीसरे प्रयास में 85 किलो वजन सफलतापूर्वक उठाया। चानू का यह प्रयास कॉमनवेल्थ गेम्स का महिलाओं के स्नैच में रिकॉर्ड प्रदर्शन है। चानू पहले प्रयास में 82 किलो नहीं उठा पाई थीं, लेकिन दूसरे प्रयास में उन्होंने 82 किलो का वजन उठाया। चानू ने इस प्रदर्शन के दम पर पहले गेम्स रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके बाद चानू ने 85 किलो वजन उठाने का फैसला किया और वह सफल रहीं। चानू का यह प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स में स्नैच का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। चानू से पहले कोई भी महिला भारोत्तोलक स्नैच वर्ग में 85 किलो वजन नहीं उठा सकी है।

रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से बनाया दबदबा

यह सिर्फ मीराबाई चानू के लिए एक और स्वर्ण पदक नहीं था, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले दबदबे की कहानी थी। भारतीय भारोत्तोलक स्टार महिलाओं की 48 किलोग्राम स्पर्धा में चार रिकॉर्ड अपने नाम कर गईं। उन्होंने पहले 82 किलोग्राम के भार के साथ राष्ट्रमंडल खेलों का एक नया स्नैच रिकॉर्ड बनाया और फिर इसे बढ़ाकर 85 किलोग्राम कर दिया, जिससे एक नया राष्ट्रमंडल स्नैच रिकॉर्ड स्थापित हुआ। क्लीन एंड जर्क में मीराबाई के 105 किलोग्राम के सफल प्रयास ने एक नया राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड बनाया और उनका कुल 190 किलोग्राम का कुल वजन भी राष्ट्रमंडल खेलों का एक नया कुल रिकॉर्ड बन गया। भारत की महानतम भारोत्तोलकों में से एक चानू के लिए यह एक ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक की हैट्रिक लगाई।

पहले प्रयास में चूकीं, दूसरे में खेल किया खत्म

मीराबाई ने स्नैच में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन से यह दिखा दिया था कि स्वर्ण पदक उनकी मुट्ठी में है। मीराबाई ने क्लीन एंड जर्क में 105 किलो वजन रजिस्टर कराया। चानू सबसे आखिर में आईं और उनका पहला प्रयास सफल नहीं रहा। दूसरे प्रयास में उन्होंने आराम से 105 किलो वजन उठाया और नियोग को पीछे छोड़ दिया। यह क्लीन एंड जर्क में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है। मीराबाई ने ग्लासगो में चुनौती पेश करने से पहले कहा था कि वह राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पूरा दम नहीं दिखाएंगी, लेकिन उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा।

राष्ट्रगान के दौरान छलक पड़े आंसू

मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। मेडल सेरेमनी के दौरान जब चानू पोडियम पर खड़ी थीं और भारत का राष्ट्रगान बजा तो वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं। मालूम हो कि स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का पोडियम पर खड़े होने के दौरान राष्ट्रगान बजाया जाता है।

एनटीए में बड़े बदलाव की तैयारी : नंदन नीलेकणि की टीम संभालेगी परीक्षा सुधार की कमान

नंदन नीलेकणि | एस. सोमनाथ | तपन डेका | वी. कामकोटि | अनीता करवाल | अमृत लाल मीणा

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक विवाद और परीक्षाओं में धांधली के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। देश भर की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने छह विशेषज्ञों की एक हाई-पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। इस उच्चस्तरीय समिति का नेतृत्व आईटी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक और देश के जाने-माने तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणि को सौंपा गया है। इस पूरी टीम में शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है, ताकि एक बेहद मजबूत परीक्षा ढांचा तैयार किया जा सके।

क्या करेगी यह टास्क फोर्स?

केंद्र सरकार ने इस समिति को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की पूरी परीक्षा प्रणाली की नए सिरे से समीक्षा करने की जिम्मेदारी दी है। यह टास्क फोर्स परीक्षा की हर प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए अपने सुझाव सौंपेगी। इसके अलावा, यह समिति साइबर सुरक्षा को अभेद्य बनाने, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था में बड़े सुधार करने और परीक्षा संचालन में समय के अनुसार जरूरी बदलाव करने की सिफारिशें भी तैयार करेगी।

कौन हैं नंदन नीलेकणि और उनके पांच दिग्गज सहयोगी?

आईटी कंपनी इंफोसिस के सह-संस्थापक हैं और भारत की आधार परियोजना को लागू करने वाली संस्था UIDAI के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। डिजिटल तकनीक, बड़े डाटा सिस्टम और सरकारी डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाने का उनका अनुभव एनटीए के लिए तकनीकी रोडमैप तैयार करने में सबसे अहम साबित होगा।

कारगिल विजय दिवस हमें वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है- मन की बात में बोले पीएम मोदी

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' के 136वें एपिसोड में देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कारगिल युद्ध के वीर शहीदों और सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह दिन देश के वीर जवानों के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित 'मन की बात' के 136वें एपिसोड में कारगिल विजय दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि यह दिन हर भारतीय को गर्व से भर देता है और देश के वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मध्य-प्रदेश के सीधी जिले में करीब डेढ़ हजार तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र-प्रदेश के नंद्याल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र-प्रदेश के विजयनगरम में इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहेजने के इस अभियान को जन-आंदोलन बनाएं...इसके तहत बारिश के पानी के संरक्षण, भूजल पुनर्भरण, पुराने जल-स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हों या शहर, पंचायतें हों या सामाजिक संस्थाएं हर जगह लोगों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है।

उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में खेलों में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल की ऊंची चोटियां, कठिन मौसम और दुश्मन की चुनौतियों के बावजूद भारतीय सैनिकों का हौसला हर परिस्थिति से बड़ा साबित हुआ। उन्होंने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों और देश की रक्षा में योगदान देने वाले सभी सैनिकों को नमन करते हुए उनके बलिदान को राष्ट्र के लिए प्रेरणास्रोत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने सैनिकों के अदम्य साहस के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में तकनीकी क्षमताओं को भी लगातार मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था देश की सुरक्षा को नई मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वीर सैनिकों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लेने तथा राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

तेज प्रताप की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन- रोहिणी आचार्य

पटना । नीट पेपर लीक मामले में छात्र आंदोलन में शामिल हुए जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है। अपने भाई की गिरफ्तारी पर रोहिणी आचार्य भी भड़क गई हैं।

उन्होंने इसे सम्राट चौधरी की सरकार की तानाशाही करार दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन और पुलिस बल का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को डराने और जन आंदोलनों के प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा, "बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना है बिहार, क्या शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मांग के साथ जारी छात्रों-युवाओं के आंदोलन, प्रदर्शन को समर्थन देना अपराध है?" उन्होंने आगे लिखा, "सम्राट सरकार की पुलिस की ओर से तथ्यहीन और झूठे आरोपों में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया जाना साफ तौर पर लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। छात्रों, युवाओं और जनता की समस्याओं के लिए आवाज उठाना हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार एवं दायित्व है। अपने इस अधिकार और दायित्व का निर्वहन करने की ऐवज में बदले की भावना से गिरफ्तारी की गयी है। रोहिणी आचार्य ने सरकार को घेरते हुए ये भी कहा, "विरोध प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया जाना स्पष्ट तौर पर सरकार के खिलाफ उभरे असंतोष को दबाने की दमनात्मक तानाशाही कार्रवाई का हिस्सा है।" उन्होंने सवाल किया, "ये कैसा न्याय है, ये कैसा चलन है?

ये कैसी रीत है? जिसमें सात खून का आरोपी मुख्यमंत्री बन जाता है और देश के युवा भविष्य के लिए आवाज उठानेवाले, संघर्ष करने वाले बेगुनाह को झूठे आरोपों में फंसा कर जेल भेज दिया जाता है?" बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के प्रमुख तेज प्रताप यादव को पटना की एक अदालत ने रविवार (26 जुलाई) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तेज प्रताप को नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में शनिवार (25 जुलाई) को रात को गिरफ्तार किया गया था।

पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर- राजनाथ सिंह

लद्दाख । कारगिल विजय दिवस समारोह में भाग लेने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को खूब खरीखोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। अगर कोई बातचीत होगी भी, तो सिर्फ पीओके पर होगी, जो भारत का हिस्सा है जिसपर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'हमारे बहादुर सैनिकों ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। हमने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक वर्ष पूरा किया है। ऑपरेशन के दौरान हमारी जांबाज सेना के जवानों और अधिकारियों ने आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब दिया है, जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे...भारत पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके देने की क्षमता रखता है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी खत्म नहीं हुआ गतिरोध, अब पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ा विपक्ष

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विपक्ष अब छात्र पर कथित पुलिस बर्बरता को लेकर संसद में सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहा है। वे हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्ष की आगे की रणनीति, जिसमें पेपर लीक विरोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन पर उनका रुख भी शामिल है। सोमवार के राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के चैंबर में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में तय की जाएगी। ये घटनाक्रम 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पर संसद में होने वाली तीखी बहस से पहले हो रहा है। इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पेश करने, उस पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले के लिए जवाबदेही की मांग की और सवाल किया कि क्या गृह मंत्री ने पैलेट गन समेत जानलेवा बल के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। पत्र में कांग्रेस सांसद ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की नींव है और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा करना तथा बातचीत के जरिए उनकी शिकायतों का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है।

कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग

कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कथित पुलिस कार्रवाई के लिए माफी मांगनी चाहिए। खरगे ने कहा कि अब प्रधानमंत्री की बारी है कि वे माफी मांगें और प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी, डंडे और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे देश के भविष्य के सम्मान में और विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए कथित अत्याचारों के लिए छात्रों से माफी मांगें।

पेपर लीक विरोधी बिल पर विपक्ष तय करेगा अपना रुख

अगर सरकार और विपक्ष संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध को सुलझा लेते हैं, तो पेपर लीक के मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना है। विपक्ष यह भी तय करेगा कि 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' का समर्थन किया जाए या नहीं। प्रस्तावित कानून का मकसद परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए सजा को सख्त करना है। पेपर लीक या अन्य अनुचित साधनों में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा धोखाधड़ी से जुड़े संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

'छात्रों को मारने का किसने दिया आदेश?' पुलिस कार्रवाई पर राहुल ने शाह को लिखा पत्र

नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 20 जुलाई को जंतर मंतर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर जवाबदेही तय करने, पैलेट गन के इस्तेमाल करने की जांच कराने और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांधी ने शनिवार को लिखे इस पत्र को सार्वजनिक करते हुए रविवार को कहा कि छात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय सुरक्षा बलों ने उन पर अंधाधुंध बल प्रयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई में पैलेट गन, आंसू गैस और अन्य घातक साधनों का इस्तेमाल किया गया, जिससे सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि महिला छात्राओं के साथ भी पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया और जानबूझकर उनको निजी स्तर पर निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर आरोप पैलेट गन के इस्तेमाल का है। मीडिया और सोशल मीडिया में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कई लोग, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है, पैलेट गन के इस्तेमाल से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्होंने 19 वर्षीय साहिल लोचाब से मुलाकात की, जो गंभीर पीड़ा में है और पैलेट गन लगने के कारण उसकी एक आंख की रोशनी जाने की आशंका है। गांधी ने कहा कि दिल्ली में तैनात सुरक्षा बल अंततः गृह मंत्री के प्रति जवाबदेह हैं। उन्होंने शाह से पूछा कि क्या गृह मंत्री के रूप में उन्होंने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन सहित घातक बल के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। यदि नहीं, तो इसकी अनुमति किसने दी। उन्होंने यह भी पूछा कि सादे कपड़ों में लाठी लेकर छात्रों को पीटते दिखाई देने वाले लोग पुलिसकर्मी थे या स्वयंसेवक तथा उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई। गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उनकी शिकायतों का समाधान संवाद के माध्यम से करे। छात्रों पर हुई बर्बर हिंसा ने लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है और पूरे देश को आक्रोशित किया है। उन्होंने कहा कि युवा और छात्र देश का भविष्य हैं तथा वे जवाब और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता और उसे हर हाल में सुना जाना चाहिए।

पीएम मोदी की छवि सुधारने की कवायद

नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स पर कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस टास्क फोर्स के गठन की आलोचना की।

नई दिल्ली । कांग्रेस ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खराब हो चुकी छवि सुधारने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को सोशल मीडिया पर इस टास्क फोर्स के गठन की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'दोस्तों, जून 2024 में नीट-यूजी सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बाद मोदी सरकार ने परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारु और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए डॉ. के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी।' जयराम रमेश ने आगे कहा, 'जुलाई 2026 में, जब मोदी सरकार एक बार फिर नीट-यूजी और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ियां रोकने में विफल रही है, तब उसने परीक्षा सुधारों पर ध्यान देने के लिए एक 'उच्चाधिकार प्राप्त टास्क फोर्स' का गठन किया है।'

जयराम रमेश बोले- राधाकृष्णन समिति की सिफारिशें ही नहीं लागू कर पाई सरकार

कांग्रेस नेता ने कहा, 'मोदी सरकार अब तक के. राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। बल्कि 2024 और 2026 के पेपर लीक के बीच लगभग दो वर्षों तक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में पूर्णकालिक महानिदेशक तक नियुक्त नहीं किया गया।' उन्होंने आरोप लगाया, 'आखिरकार यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री की अपूरणीय रूप से खराब हो चुकी छवि सुधारने की एक उच्चस्तरीय कोशिश मात्र है।' 'इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

बड़ा ऐलान- 'नहीं लड़ूंगा 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव': पूर्व सीएम सिद्धारमैया

बंगलूरू । कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने रविवार को बड़ा एलान किया। सिद्धारमैया ने ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि वह 2028 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने इसके लिए अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 79 वर्ष का हूं।

सक्षम भारत

सक्षम भारत की बेवसाईड से जुड़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्केन करे।